

साथ-साथ पंजाब और हरियाणा के शेषजल में उनके हिस्से से संबंधित दावों पर निर्णय देने के लिए भारत सरकार द्वारा रावी और व्यास जल अधिग्रहण (आर0बी0डब्ल्यू0 टी0) का गठन किया गया था। रावी और व्यास अधिकरण ने दिनांक 30.1.87 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस संबंध में पाये गये तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद रावी-व्यास अधिकरण की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार तथा साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से प्राप्त संदर्भों को अधिकरण को भेजा गया था। यह मामला अभी भी रावी-व्यास जल अधिकरण के विचाराधीन है।

जल प्रबन्धन के लिए सरदार सरोवर निगम का मास्टर प्लान

1390. श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वैज्ञानिक जल-प्रबंधन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च को अद्यतन बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संसाधन जुटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं। गुजरात सरकार के पूर्ण स्वामित्व में सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहभागी राज्यों को लाभ

पहुंचाने वाले नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या

1391. श्री ओंकार सिंह लखावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग (सैम) की समस्या के संबंध में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने वाटर-लॉगिंग की समस्या के निदान हेतु विशेषज्ञों का कोई दल तैयार कर राजस्थान में भेजा है; यदि हां, तो कब; और

(ग) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कुल कितना क्षेत्र वाटर लॉगिंग से प्रभावित हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान में जल जमाव वाले क्षेत्रों का पता लगाया है।

(ख) जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के एक दल सहित जुलाई, 1997 में राजस्थान के झंझुनु चुरु, सरदार शहर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों में दौरा किया। इस टीम ने इन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या का अध्ययन किया।

(ग) राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर कमान में जल जमाव वाले क्षेत्रों का आकलन किया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

	चरण-I	चरण-II	कुल
(i) जल जमाव वाला क्षेत्र (भू स्तर के नीचे 1.0 मीटर तक जल स्तर)	17220	1243	18463
(ii) क्रिटिकल क्षेत्र (भू-स्तर के नीचे 1.0-1.5 मीटर के मध्य जल स्तर)	24140	3610	27750
(iii) पोटेंशियली सॉसिटिव एरिया (भू-स्तर के नीचे 1.5-6.0 मीटर तक जल स्तर)	297620	17303	315123